जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

चूरू

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 16 संख्याः 209 प्रभात चूरू, मंगलवार 26 नवम्बर, 2024 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

15 साल राज किया, पर 15 सीटों पर सिमटी कांग्रेस महाराष्ट्र में

क्या राहुल गाँधी कांग्रेस को चुनाव जिताने में असक्षम एवं असफल साबित हो गए हैं

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 नवम्बर। क्या राहुल गांधी कांग्रेस को एक ऐसी सुसंगत, एकजुट तथा चुनाव जीतने वाली पार्टी का रुप देने में असफल हो गये हैं, जिसकी संगठनात्मक जड़ें गहरी हों तथा जिसकी विभिन्न कमेटियों में ऐसे नेता हों, जो सत्यनिष्ठा के साथ काम कर सकते हों?

महाराष्ट्र में कांग्रेस की जबरदस्त पराजय बता रही है कि सब कुछ ठीक-ठाक नहीं है। महाराष्ट्र में 15 साल कांग्रेस का शासन रहा और 288 सदस्यों वाली विधानसभा में उसके पास केवल 15 सीट हैं।

राहुल गांधी विभिन्न राज्यों में कार्यालय प्रभारी नियुक्त करने में एक चुनाव-जिताऊ तन्त्र बनाने में तथा निष्ठा से काम करने वाले नेताओं को आगे लाने में असमर्थ रहे हैं।

उनकी समस्या यह है कि उनके पास ऐसे चन्द गिने-चुने नेता हैं, जिन पर वे भरोसा करते हैं, जिन पर उन्हें विश्वास है और उन्होंने उन नेताओं को निर्णय लेने की नियुक्तियाँ करने की, रणनीति तय करने की तथा अपने हिसाब से पार्टी चलाने की छूट दे रखी है।

- कमज़ोर संगठन और ईमानदारी के साथ पार्टी के लिए काम करने वाले नेताओं के संकट से जूझ रही पार्टी में अधिकांश राज्यों में संगठन के प्रमुख पद खाली पड़े हैं।
- असल में राहुल कुछ ही नेताओं पर भरोसा करते हैं और ये नेता अपनी मर्जी से राहुल को चलाते हैं। इनमें सबसे पहला नाम है के.सी. वेणुगोपाल का, जो राहुल के दाएं हाथ माने जाते हैं।
- लेकिन अब वेणुगोपाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रियंका गांधी के रूप में पार्टी में नया पावर सैंटर उभर रहा है और वेणुगोपाल को अब अगर अपना पद बचाना है तो प्रियंका को भी प्रसन्न रखना होगा।
- वर्ष 2019 के बाद से कांग्रेस ने कई चुनाव हारे हैं पर किसी ने भी हार से कोई सबक नहीं सीखा। हार के लिए किसी की भी जिम्मेवारी तय नहीं की जाती है। जिन नेताओं के नेतृत्व में पार्टी को राज्यों में शर्मनाक हार मिली वे आज भी संगठन में महत्वपूर्ण बने हुए हैं, शायद यही कारण है कि एक हार के बाद पार्टी अगली हार की ओर बढ़ जाती है।

इनमें सबसे पहले आते हैं, के.सी. वेणुगोपाल, जो राहुल के दाहिने हाथ हैं तथा जो सारे महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं तथा नियुक्तियाँ करते हैं।

वे वायनाड में प्रियंका गांधी के पीछे लगे रहने पर इतना ध्यान दे रहे थे, मानों उन्हें प्रियंका को अपनी प्रति पूरी तरह अनुकूल बनाये रखना हो, क्योंकि वे कांग्रेस में सत्ता के एक बड़े केन्द्र के रूप में उभरने ही वाली हैं। अगर वेणुगोपाल अपने पद को बनाये रखना चाहते हैं, तो अब उनको प्रियंका गांधी के इर्द-गिर्द चक्कर लगाते ही रहने होंगे।

वेणुगोपाल का ध्यान महाराष्ट्र या झारखंड के चुनावों की तरफ बिलकुल भी नहीं था।

हरियाणा में मिली अप्रत्याशित हार के बाद, कांग्रेस वहाँ से कोई सबक सीखने में असफल रही। कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई, कोई आत्म-निरीक्षण नहीं किया गया, और अब पार्टी को महाराष्ट्र के नतीजों का सामना करना है। नाना पटोले ने अपने इस्तीफे की पेशकश की, लेकिन समझा जाता है कि उनसे कह दिया गया बताते हैं कि वे एक नई समस्या पैदा नहीं करें, क्योंकि फिर अन्य लोगों पर भी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी।

एक मीटिंग में, राहुल गांधी के चन्द गिने-चुने नवरत्नों ने उन्हें विश्वास दिलाया कि ई.वी.एम. हैक नहीं की जा सकतीं। इनमें से कई नेता, वरिष्ठ भाजपा नेताओं के सम्पर्क में माने जाते हैं क्योंकि उन्हें उनके खिलाफ केस बनाये जाने का डर है या फिर कुछ अन्य कारण हैं।

पार्टी में यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या समय आ गया है कि राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनने का निर्णय

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अडानी और मणिपुर की भेंट चढ़ा शीतकालीन सत्र का पहला दिन

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 25 नवंबर। संसद के शीत सत्र के पहले ही दिन लोकसभा तथा राज्यसभा, दोनों को व्यवधान का सामना करना पड़ा क्योंकि, विपक्षी दल के नेता अडानी रिश्वत केस तथा मणिपुर हिंसा पर अविलंब चर्चा की मांग करते रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने, सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालने के, विपक्ष के प्रयास की आलोचना की। संसद की कार्यवाही अब बुधवार को फिर शुरू होगीं, क्योंकि, मंगलवार को दोनों सदनों में संविधान के 75 वर्षों का जश्न मनाया जाएगा।

विपक्षी दल इस मुद्दे पर एकजुट हैं कि अडानी पर रिश्वत आरोपों की जवाबदेही सरकार की है, जबकि, शीत सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री की टिप्पणियां, सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाती हैं।

- पहले दिन ही लोकसभा पूरे दिन के लिए स्थगित, अब बुधवार को पुनः काम शुरू होगा।

लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने आज लगभग एक घंटे के लिए, दोपहर 12 बजे तक सदन को स्थगित कर दिया और बाद में 12 बजे जब सदन की कार्यवाही पुनः शुरू हुई तो, पीठासीन अधिकारी संध्या रे ने उनके तुरंत बाद लोकसभा को बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया। कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दलों ने धरना प्रदर्शन करके अडानी के विरूद्ध रिश्वत के आरोपों मामलों और मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग की।

गत सप्ताह, विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक, गौतम अडानी व सात अन्य पर अमेरिका के सरकारी वकीलों ने दोषारोपण किया था। इन लोगों पर आरोप था कि, सोलर पावर सप्लाई कांट्रैक्ट हासिल करने के लिए इन्होंने कई राज्यों के भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी। अडानी ग्रुप ने इन आरोपों

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमित शाह देवेन्द्र फड़नवीस को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं

अमित शाह ने देवेन्द्र फड़नवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार से मीटिंग कर फॉर्मूला तय किया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 नवम्बर। भाजपा नेता देवेन्द्र फड़नवीस, जो जाति से ब्राह्मण हैं, तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आधे कार्यकाल अर्थात ढाई साल बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी एकनाथ शिंदे को मिलेगी। शिंदे और पवार उपमुख्यमंत्री बनेंगे।

यह फॉर्मूला केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने तीनों नेताओं से मुलाकात करने के बाद निकाला है। सूत्रों का कहना है कि शिंदे मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे पर जब शाह ने उनसे वादा किया कि आधे कार्यकाल के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा और अगले चुनाव के समय वे ही मुख्यमंत्री होंगे तब जाकर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा छोड़ने के लिए माने। नई सरकार संभवतया मंगलवार को शपथ लेगी।

महायुति सरकार की नई व्यवस्था में शिंदे सेना के 12 मंत्री होंगे और एन.सी.पी. के दस।

शुरु के ढाई साल तक देवेन्द्र फड़नवीस मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे और चर्चा है कि ढाई साल बाद जब फड़नवीस मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र दे देंगे तब उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तब तक केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर कार्यकाल में एक बार फिर विस्तार दिया जा सकता है।

- नए फार्मूला के तहत, शुरू के ढाई साल देवेन्द्र फड़नवीस मुख्यमंत्री बनेंगे और बाद के ढाई साल एकनाथ शिंदे।
- शिंदे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावेदारी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे पर अंततः शाह के समझाने पर वे मान गए।
- नई व्यवस्था में शिंदे और अजीत पवार को उपमुख्यमंत्री बनाया जाएगा तथा शिंदे गुट के 12 और एन.सी.पी. के 10 मंत्री होंगे।
- सूत्रों ने बताया कि ढाई साल बाद जब फड़नवीस महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे तो उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है।

खुली जेल में सैटेलाइट अस्पताल के निर्माण पर कोर्ट कमिश्नर नियुक्त

जयपुर, 25 नवंबर। सुप्रीम कोर्ट ने सांगानेर स्थित देश की पहली खुली जेल में राज्य सरकार की ओर से 300 बैड्स के सेटेलाइट हॉस्पिटल बनाए जाने के मुद्दे पर जनकल्याण व खुली जेल की व्यवस्था को संरक्षित रखते हुए, हॉस्पिटल बनाने की मंशा जताई है। इसके साथ ही, अदालत ने खुली जेल परिसर के मौका-मुआयना के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर उससे चरणबद्ध योजना व रिपोर्ट देने के लिए

- सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कमिश्नर जाँच करेगा कि खुली जेल की सुविधाएं संरक्षित रहें।

कहा है। अदालत ने कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट आने तक आगामी सुनवाई स्थगित रखी है। जस्टिस बी.आर. गवई व के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने यह आदेश प्रसून गोस्वामी की अवमानना याचिका पर दिया। अदालत ने राज्य सरकार को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि निर्माण कार्य में खुली जेल की सुविधाएं भी संरक्षित रहें। वहीं, निर्माण से पहले जेल में रहने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

झारखंड की नई विधानसभा में 71 करोड़पति विधायक

करोड़पति विधायकों की संख्या 2014 में 41 और 2019 में 56 थी

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 नवम्बर। एक चीज़ ऐसी है जो पूरे देश में सभी राजनीतिक दलों को एक सूत्र में बांधती है: चुनावों में करोड़पतियों की संख्या उदाहरण के लिए झारखंड में चयनित करोड़पतियों की संख्या 2014 में 41 थी जो कि 2019 में बढ़कर 56 हो गई। ये आंकड़े, झारखंड इलैक्शन वॉच एण्ड द एसोसिएशन ऑफ डैमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने जारी किए हैं। हाल ही में सम्पन्न हुए चुनावों में भी यही ट्रैंड देखा गया और इस बार नवनिर्वाचित विधायकों में से 89 प्रतिशत विधायकों की संपत्ति करोड़ों की है। दूसरे शब्दों में, नवनिर्वाचित विधायकों में से 71 विधायक करोड़पति पाए ग, जो कि 2019 के ऐसे विधायकों से 20 प्रतिशत अधिक है। ऐसे अमीर विधायक सभी राजनीतिक दलों में है।

कांग्रेस के रामेश्वर ओरांव इस बार सबसे अमीर विधायक के रूप में सामने आए हैं। उनकी संपत्ति 42.20 करोड़ की आंकी गई है।

भाजपा के कुशवाहा शशि भूषण मेहता, जो पनकी विधान सभा सीट से विजयी रहे हैं। दूसरे नम्बर के सबसे अमीर विजयी प्रत्याशी हैं। इनकी कुल संपत्ति 31.15 करोड़ मूल्य की है। रिपोर्ट के अनुसार गोड्डा सीट से जीतने वाले आर.जे.डी. के संजय प्रसाद यादव, 29.59 करोड़ की कुल संपत्ति के साथ इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- करोड़पति विधायकों में पहले नम्बर पर हैं कांग्रेस के रामेश्वर ओरांव, जिनकी सम्पत्ति 42.20 करोड़ रु है। दूसरे नम्बर पर भाजपा विधायक कुशवाहा शशि भूषण मेहता और तीसरा नम्बर है आर.जे.डी. के संजय प्रसाद यादव का।
- 71 करोड़पति विधायकों में से सर्वाधिक 28 विधायक आदिवासियों की पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं और 20 भाजपा से। कांग्रेस के करोड़पति विधायकों की संख्या 14 है, आर.जे.डी. के 5 तो सी.पी.आई.एम.एल. (लिबरेशन) के चार व एल.जे.पी., जद (यू) और ए.जे.एस.यू. का एक-एक विधायक करोड़पति है।
- ये आंकड़े झारखंड इलैक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डैमोक्रैटिक रिफॉर्म्स ने संयुक्त रूप से जारी किए हैं।

दो से ज्यादा संतान वालों की पदोन्नति की राह खुली

जयपुर, 25 नवंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कार्मिक विभाग के 16 मार्च, 2023 की अधिसूचना के आधार पर, दो से ज्यादा संतान वाले कर्मचारियों को संबंधित सालों से पदोन्नत करने के मामले में रोक लगाने के आदेश को संशोधित कर दिया है। इसके साथ ही, अदालत ने पदोन्नति पर लगी रोक को

- कार्मिक विभाग ने दो से ज्यादा संतान वालों की पदोन्नति के बारे में मार्च 2023 में अधिसूचना जारी की थी। अदालत ने इस अधिसूचना पर रोक लगा दी थी। आज चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने यह रोक हटा दी।

हटाते हुए, होने वाली पदोन्नितयों को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रखा है। चीफ जस्टिस एम.एम. श्रीवास्तव और जस्टिस उमाशंकर व्यास की खंडपीठ ने ये आदेश संतोष व अन्य की याचिका पर राज्य सरकार की ओर से दायर स्टे प्रार्थना पत्र पर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिल्ली में मनमानी राजनैतिक नियुक्तियां कीं वेणुगोपाल ने

पार्टी सूत्रों के अनुसार, वेणुगोपाल ने जाति, धर्म और क्षेत्रवार संतुलन को पूरी तरह नज़र अंदाज किया

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 नवम्बर। कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी कहा गया है, जो मुसलमानों के हितों और कल्याण पर फोकस करती है।

कांग्रेस ने दिल्ली कांग्रेस में की गई नियुक्तियों से इस बात को सही साबित कर दिया है।

काज़ी निज़ामुद्दीन को सचिव पद से पदोन्नत करके दिल्ली का ए.आई.सी.सी. इन्चार्ज बनाया है। कहा जाता है कि उन्हें के.सी. वेणुगोपाल का आशीर्वाद प्राप्त है, इन नियुक्तियों के पीछे उन्हीं का हाथ है, जिनमें जाति, धर्म या क्षेत्र के आधार पर संतुलन का ध्यान नहीं रखा गया है। वो ''सोशल इंजिनियरिंग'' जैसे शब्दों से अवगत नहीं हैं, और इस सिद्धांत पर काम करते हैं कि मेरा आदमी सर्वश्रेष्ठ है।

इसके साथ ही दानिश अबरार को दिल्ली के लिए सचिव नियुक्त किया गया है। दिल्ली की स्क्रीनिंग कमेटी में, सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद को सदस्य बनाया गया है।

वरिष्ठ नेताओं से जब इस बारे में पूछा गया तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। दिल्ली और हरियाणा के प्रभारी, बीमार चल रहे बाबरिया को उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त किया गया है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- सूत्रों ने कहा कि वेणुगोपाल शायद नहीं जानते कि राजनीति में ''सोशल इंजीनियरिंग'' कितनी महत्वपूर्ण है, उन्हें तो लगता है कि जो उनका 'यस मैन'' है, वही सही है।
- दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं और वेणुगोपाल ने पार्टी संगठन व चुनाव प्रबंध से जुड़े कई महत्वपूर्ण पदों पर मुस्लिम समाज के नेताओं को नियुक्ति दे दी है, इससे पार्टी पर तुष्टिकरण के आरोप लगने शुरू हो गए हैं।
- लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस की यही कहानी है, राहुल ने पार्टी में अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी वेणुगोपाल को दे रखी है।
- पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मजबूर हैं, इतने मजबूर कि वे वेणुगोपाल व जयराम रमेश को हटाना चाहते हैं पर हटा नहीं पा रहे हैं।

नीट यूजी : स्ट्रे वेकैन्सी में आवंटन निरस्त करने पर रोक

जयपुर, 25 नवंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने नीट यूजी-2024 के स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आवंटित सीट को निरस्त करने वाले एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही, अदालत ने

- एकल पीठ ने 11वीं के प्रमाण पत्र में बायोलॉजी उल्लेख नहीं होने के मामले में सीट आवंटन को निरस्त कर दिया था, हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उक्त आदेश पर रोक लगा दी।

कहा है कि यदि एकलपीठ के याचिकाकर्ता इसमें शामिल होते हैं तो उन्हें मेरिट के अनुसार सीट आवंटित की जाए। चीफ जस्टिस एम.एम. श्रीवास्तव और जस्टिस उमाशंकर व्यास की खंडपीठ ने ये आदेश जतिन और नीतू

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'आरोप अडानी पर है, और तकलीफ भाजपा को हो रही है'

विपक्षी दलों ने केन्द्र सरकार पर निशाना साधा और यह भी कहा कि भाजपा सरकार इस मुद्दे पर चर्चा करने से डरती है

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 नवम्बर। कांग्रेस लोक सभा सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार अडानी के मुद्दे पर चर्चा करने से ''बहुत ज्यादा भयभीत'' है।

वेणुगोपाल ने कहा, ''वे (सरकार) इस मुद्दे पर विपक्ष का एक शब्द भी सुनने के लिये तैयार नहीं हैं। एक सैकंड के अन्दर ही उन्होंने सदन स्थगित कर दिया। वे इस मुद्दे को उठाये जाने से डरे हुये हैं।''

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि दोनों पक्षों को परस्पर सहयोग करने की जरूरत है ताकि सदन का चलना सुनिश्चित हो सके।

तिरूवन्तपुरम के लोक सभा सांसद शशि थरूर ने कहा, ''सभी विपक्षी दल इस मुद्दे पर बहस करना चाहते थे किन्तु सरकार तैयार नहीं थी। इस मुद्दे पर बिजनेस एडवाइज़री कमेटी में चर्चा होनी चाहिये। मुख्य बात यह है कि हर सदस्य को सदन चलने देना चाहिए, सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिये।''

उन्होंने आगे कहा, ''एक सांसद होने के नाते, मैं यहाँ आना और बहस करना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिये दोनों पक्षों की ओर से सहयोग की जरूरत है।''

राज्य सभा के आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि अडानी के खिलाफ गम्भीर आरोप हैं, जिन पर चर्चा होना जरूरी है।

उन्होंने कहा, ''मोदी सरकार संसद को नहीं चलने दे रही। हम चाहते हैं कि अडानी के भ्रष्टाचार पर चर्चा हो। इसके कारण, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सारी दुनिया में भारत की बदनामी हो रही है।''

- कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि सभी विपक्षी दल इस मसले पर चर्चा करना चाहते हैं, पर सरकार नहीं चाहती।
- आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि अडानी ने मोदी सरकार के अफसरों को रिश्वत दी और देश की जनता को महंगी बिजली बेची।
- तृणमूल पार्टी की एक सांसद डोला सेन ने आरोप लगाया कि किसी ने भी धरना नहीं दिया फिर भी दो बार संसद स्थगित हुई और दूसरी बार तो पूरे दिन के लिए, और वो विपक्ष पर आरोप लगा रही है।
- विपक्ष का विरोध संसद तक ही सीमित नहीं है। इंडियन यूथ कांग्रेस ने जंतर मंतर पर भी धरना प्रदर्शन दिया।
- चर्चा है कि अडानी पर विदेश में मामला दर्ज हुआ है। अब अगला कदम क्या होगा, फिलहाल अडानी कहां हैं, यह पता नहीं है, समझा जाता है कि वे भारत में ही कहीं हैं।

सिंह ने आरोप लगाया, ''अडानी ने मोदी सरकार के अधिकारियों को रिश्वत दी तथा भारत की जनता को महँगी बिजली बेची, हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रतिस्पर्धी बिल्डिंग होनी चाहिये। सरकार चर्चा से भाग रही हैं।''

तृणमूल कांग्रेस सांसद डोला सेन ने कहा कि ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष चाहता ही नहीं कि सदन चले, क्योंकि कोई भी हंगामा या शोरगुल न होने के बावजूद, सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।

उन्होंने जोर देते हुये कहा, ''..किसी ने कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन दो बार स्थगन हुआ। यह सत्ता पक्ष की नीति है, वे हर पल अनावश्यक रूप से दोषारोपण कर रहे हैं।

अमेरिकन प्रॉसिक्यूटर्स ने अडानी पर आरोप लगाया है कि वे, कथत रूप से सौर ऊर्जा अनुबन्धों के लिये उनके अनुकूल शर्तें रखने के बदले में, भारतीय अधिकारियों को 250 मिलियन डॉलर (करीब 22,000 करोड़ रु.) से अधिक रिश्वत देने की योजना के हिस हैं।

अडानी ग्रुप ने इस आरोपों को निराधार बताते हुये खारिज कर दिया है।

इस मुद्दे को लेकर सरकार पर विपक्ष का हमला संसद तक ही सीमित नहीं था।

इंडियन यूथ कांग्रेस ने सोमवार को दिल्ली में जन्तर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन किया तथा गौतम अडानी की गिरफ्तारी की माँग की।

प्रदर्शन का नेतृत्व इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब ने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)